



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2019/आषाढ़ 7, 1941

No. 178]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2019/ASHADHA 7, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2019

(ओ आई प्रकरण सं. 07/2019)

**विषय: यूरोपीय संघ, जापान, यूएसए और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कोटेड/प्लेटेड टिन मिल फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पादों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

**फा. सं. 6/9/2019-डीजीटीआर.**—मै. जे एस डब्लू वल्लभ टिनप्लेट प्रा. लि. और मै. दि टिनप्लेट कंपनी आफ इंडिया लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता या आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें यूरोपीय संघ, जापान, यूएसए और कोरिया गणराज्य से कोटेड/प्लेटेड टिन मिल फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पादों (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

## विचाराधीन उत्पाद

- वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ("पीयूसी") टिन मिल फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद है जो टिन या क्रोमियम / क्रोमियम ऑक्साइड के साथ एक तरफ या दोनों तरफ, चाहे लेकर्ड और/या मुद्रित हो अथवा नहीं द्वारा कोटेड या प्लेटेड हों। टिन मिल फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पादों में टिन प्लेट के साथ-साथ टिन-मुक्त स्टील भी शामिल है, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी), टिन फ्री स्टील (टीएफएस), इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम कोटेड स्टील (ईसीसीएस)

- के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद को कॉइल के रूप में या शीट/स्कॉल के रूप में आपूर्ति की जा सकती है। शीट/स्कॉल सहित विभिन्न आकारों वर्ग, आयत, वृत्त या किसी भी अन्य आकार तक, साथ या बिना खाली किए बिना परंतु इन तक सीमिति नहीं सहित आपूर्ति की जा सकती है।
3. विचाराधीन उत्पाद आम तौर पर बहुमुखी पैकेजिंग समाधानों के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें खाद्य पैकेजिंग, अर्थात् खाद्य तेल, प्रसंस्कृत खाद्य, फल, सब्जियां, पेय पदार्थ आदि के साथ-साथ गैर-खाद्य पैकेजिंग, अर्थात् पेंट, रसायन, खाद्य तेल, ज्यामिति / कम्पास बॉक्स, जूता पॉलिश, एयरोसोल स्प्रे, बैटरी, आदि के लिए है परंतु इन तक सीमित नहीं है।
4. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की टैरिफ मद 72101110, 72101190, 72101210, 72101290, 72105000, 72109010, 72121010, 72121090, 72125020, 72121010, 72125090 और 72259900 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि पीयूसी के आयात सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के कतिपय अन्य आईटीसी एचएस कोडों अर्थात् 72109090, 72107000, 72103090, 72255010, 72124000 के अधीन भी देखे गये हैं।
5. सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।
- समान वस्तु**

6. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

*“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;*

7. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि उनके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु समान वस्तुएं हैं। संबद्ध देशों से निर्यातित और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित कोटेड/प्लेटेड टिन मिल फ्लैट रोलड स्टील उत्पाद अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और इसलिए नियमावली के अधीन उन्हें "समान वस्तु" माना गया है। अतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना गया है।

### **घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

8. यह आवेदन मेसर्स जेएसडब्लू वल्लभ टिनप्लेट प्रा. लिमिटेड और दि टिनप्लेट कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पीयूसी के घरेलू उद्योग के रूप में दायर किया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे भारत में पीयूसी के प्रमुख उत्पादक हैं जिनका पीओआई के दौरान कुल भारतीय उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है। याचिकाकर्ताओं ने प्रमाणित किया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा या उनके किसी संबंधित पक्षकार द्वारा संबद्ध देशों से पीयूसी के कोई आयात नहीं किए गए हैं और वे संबद्ध देशों में पीयूसी के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित नहीं है अथवा भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित नहीं है।
9. याचिकाकर्ताओं के अलावा, भारत में पीयूसी के दो अन्य ज्ञात उत्पादक हैं अर्थात् मै. स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि. (सेल) और मै. जीपीटी लिमिटेड हैं। यद्यपि स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और जीपीटी लिमिटेड भारत में पीयूसी के उत्पादक हैं तथापि उन्होंने प्रस्तावित पीओआई के दौरान पीयूसी का उत्पादन नहीं किया है।

10. अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि याचिकाकर्ताओं का कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है और वे नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करते हैं।

### **शामिल देश**

11. वर्तमान जांच यूरोपीय संघ, जापान, यूएसए और कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

### **सामान्य मूल्य**

12. याचिकाकर्ताओं ने हाट-रोल्ड काइलों जो संबद्ध देशों में पीयूसी के निर्माण के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है की कीमतों और यूरोपीय संघ, यूएसए और कोरिया गणराज्य में प्रचलित बिजली की कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित के आधार पर सामान्य मूल्य को निम्नानुसार परिकलित किया है :
- कच्ची सामग्री : सर्वाधिक कार्यकुशल याचिकाकर्ता के खपत मानकों के साथ पीओआई के दौरान संबद्ध देशों में प्रचलित हाट-रोल्ड काइलों की कीमतों को अपनाया गया है। सर्वाधिक कुशल याचिकाकर्ता की लागत के आधार पर अन्य कच्ची सामग्री की लागत ली गई है।
  - सुविधाओं की लागत : यूरोपीय संघ, यूएसए और कोरिया गणराज्य में प्रचलित बिजली की कीमतों को सर्वाधिक कुशल याचिकाकर्ता के खपत मानकों के साथ अपनाया गया है। जापान में बिजली की लागत सर्वाधिक कुशल याचिकाकर्ता की लागत पर आधारित है। अन्य सुविधाओं की लागत सर्वाधिक कुशल याचिकाकर्ता की लागत पर आधारित है।
  - अन्य परिवर्तन लागत : अन्य परिवर्तन लागत सर्वाधिक कुशल याचिकाकर्ता की लागत पर आधारित है।
  - लाभ मार्जिन : तर्कसंगत लाभ मार्जिन पर सामान्य मूल्य ज्ञात करने के लिए विचार किया गया है।

जाँच शुरूआत के प्रयोजनार्थ परिकलित सामान्य मूल्य को अपनाया जा रहा है।

### **निर्यात कीमत**

13. याचिकाकर्ताओं ने डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत की गणना की है। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन और बैंक प्रभार के आधार पर कीमत समायोजनों को दावा किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई निवल निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।
14. सामान्य मूल्य और संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है जिससे प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन का पता चलता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे पता चलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

### **क्षति और कारणात्मक संबंध**

15. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन करने के लिए विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने पाटित आयातों की समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर नकद लाभ और

आय के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हो रही है जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराता है।

### **पाटनरोधी जाँच की शुरूआत**

16. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं। इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जाँच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

### **जाँच अवधि**

17. वर्तमान जाँच के लिए जाँच की अवधि (जिसे आगे पीओआई भी कहा गया है) 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 (12 महीने) की है। तथापि क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2015 – मार्च, 2016, अप्रैल 2016 – मार्च, 2017, अप्रैल 2017 – मार्च, 2018 की अवधि और जाँच अवधि शामिल है।

### **सूचना प्रस्तुत करना**

18. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।
19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत की जा सकती है :

#### **निर्दिष्ट प्राधिकारी**

**व्यापार उपचार महानिदेशालय**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**वाणिज्य विभाग**

**भारत सरकार**

**चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,**

**नई दिल्ली- 110001**

20. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

### **समय-सीमा**

21. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना इस जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी

पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना मूल प्रतियों और सॉफ्ट प्रतियों में अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

### गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

23. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-
- गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और
  - अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।
24. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां चार (4) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
25. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
28. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
29. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

30. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

**असहयोग**

31. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(Directorate General of Trade Remedies)**

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2019

**(OI Case No. 7/2019)**

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Coated/Plated Tin Mill Flat Rolled Steel Products originating in or exported from the European Union, Japan, USA and Korea RP.**

**F. No. 6/9/2019-DGTR.**—M/s JSW Vallabh Tinplate Private Limited and M/s The Tinplate Company of India Limited (hereinafter also referred to as the ‘Petitioners’ or ‘Applicants’) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’) for imposition of Anti-Dumping Duty on imports of Coated/Plated Tin Mill Flat Rolled Steel Products (hereinafter referred to as the ‘subject goods’ or ‘PUC’) from the European Union, Japan, USA and Korea RP.

**Product under consideration**

2. The product under consideration (“PUC”) in the present investigation is tin mill flat rolled steel products that are coated or plated with tin or chromium / chromium oxides, either on one side or both sides, whether lacquered and/or printed or not. Tin mill flat rolled steel products include Tinplate as well as Tin-free steel, which is also known as Electrolytic Tin Plate (ETP), Tin Free Steel (TFS), Electrolytic Chromium Coated Steel (ECCS). The product under consideration may be supplied in coil form or sheets / scrolls. The sheets / scrolls may be supplied in various shapes including, but not limited to, square, rectangle, circle or any other shape, with or without blanking.
3. The product under consideration is generally used for versatile packaging solutions including, but not limited to food packaging, i.e. edible oil, processed food, fruits, vegetables, beverages, etc. as well as used for non-food packaging, i.e. paints, chemicals, non-edible oil, geometry/compass box, shoe polish, aerosol sprays, batteries, etc.

4. The product under consideration is classified under tariff item 72101110, 72101190, 72101210, 72101290, 72105000, 72109010, 72121010, 72121090, 72125020, 72121010, 72125090 and 72259900 of the Customs Tariff Act, 1975. However, imports of the PUC have also been observed in certain other ITC HS codes viz. 72109090, 72107000, 72103090, 72255010, 72124000 of the Customs Tariff Act, 1975.
5. The customs classification is indicative only and in no way binding upon the scope of the product under consideration.

### Like Article

6. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

*"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*

7. The Petitioners have submitted that the subject goods produced by them and the subject goods imported from the subject countries are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and those produced by the Petitioners. Coated/Plated Tin Mill Flat Rolled Steel Products produced by the Petitioners and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Petitioners are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

### Domestic industry and Standing

8. The application has been filed by M/s JSW Vallabh Tinplate Private Limited and M/s The Tinplate Company of India Limited, as domestic industry of the PUC. According to the Petitioners, they are the major producer of the PUC in India, account for 100% of total Indian production during the POI. The Petitioners have certified that there are no imports of the PUC by the petitioners or any of their related parties from the subject countries and they are not related either to any exporter or producer of the PUC in the subject countries or any importer of the PUC in India.
9. Apart from the petitioners, there are two other known producers of the PUC in India, namely, M/s. Steel Authority of India Limited (SAIL) and M/s. GPT Limited. Even though Steel Authority of India Limited (SAIL) and GPT Limited are producers of PUC in India, they did not produce the PUC during the proposed POI
10. The Authority, therefore, determines that the petitioners hold a "major proportion" of the total domestic production and constitute an eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and also satisfy the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules.

### Countries Involved

11. The present investigation is in respect of alleged dumping of the PUC from the European Union, Japan, USA and Korea RP.

**Normal Value**

12. The Petitioners have constructed the normal value based on the price of hot-rolled coils, which is the primary raw material for making the PUC, in the subject countries and power prices prevailing in the European Union, USA and Korea RP. Accordingly, the Petitioners have calculated the normal value based on the following:

- i. Raw materials: Prices of hot-rolled coils prevailing in the subject countries during the POI along with consumption norms of the most efficient Petitioner have been adopted. Other raw material costs are based on the cost of the most efficient Petitioner;
- ii. Utilities cost: Power prices prevailing in the European Union, USA and Korea RP along with consumption norms of the most efficient Petitioner have been adopted. Power cost for Japan is based on the cost of the most efficient Petitioner. Other utilities cost is based on the cost of the most efficient Petitioner;
- iii. Other conversion cost: Other conversion cost is based on the cost of the most efficient Petitioner; and
- iv. Profit Margin: Reasonable profit margin has been considered to work out the normal value.

For the purpose of initiation, the constructed normal value is being adopted.

**Export Price**

13. The Petitioners have computed the export prices for the subject countries on the basis of data published by DGCI&S, Kolkata. Price adjustments have been claimed on account of ocean freight, inland freight, ocean insurance, commission and bank charges. There is sufficient prima facie evidence with regard to the net export prices claimed by the Petitioners.
14. The normal values and the export prices for the subject countries have been compared at ex-factory level, which prima facie show significant dumping margins in respect of the subject goods from the subject countries. There is prima facie evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are higher than the ex-factory export prices, indicating that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

**Injury & Causal Link**

15. Information furnished by the Petitioners has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Petitioners have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, price undercutting, price underselling, profitability, cash profits and return on capital employed. There is sufficient prima facie evidence of injury being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from the subject countries to justify initiation of an anti-dumping investigation.

**Initiation of Anti-Dumping Investigation**

16. And whereas, the Authority prima facie finds that evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; and injury to the domestic

industry and causal link between the alleged dumping and injury exists to justify initiation of an anti-dumping investigation. The Authority accordingly initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

### **Period of Investigation**

17. The period of investigation (hereinafter referred to as “POI”) for the present investigation is from 1<sup>st</sup> January 2018 to 31<sup>st</sup> December 2018 (12 months). The injury investigation period will, however, cover the periods April 2015-March 2016, April 2016-March 2017, April 2017-March 2018 and the POI.

### **Submission of information**

18. The known exporters in the subject countries and their governments through their embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. The information/submission may be submitted to:

#### **The Designated Authority**

#### **Directorate General of Trade Remedies**

#### **Ministry of Commerce & Industry**

#### **Department of Commerce**

#### **Government of India**

**4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street**

**New Delhi-110001**

20. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non confidential version of the same available to the other parties.

### **Time-Limit**

21. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of the publication of this initiation notification. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of the publication of this initiation notification. The information must be submitted in hard copies as well as in soft copies.

**Submission of information on confidential basis**

23. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
  - i. One set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
  - ii. Other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
24. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in four (4) sets of each.
25. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.
28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
29. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

**Inspection of Public File**

30. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

31. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority